



No. RT-11036/82/2017-MVL

भारत सरकार

Government of India

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

Ministry of Road Transport and Highways

Transport Bhawan, 1 Parliament Street, New Delhi-110001.

Dated the 1st of May, 2019

To,

The Principal Secretaries/The Secretaries, Department of Transport
The Transport Commissioners
of all the States/UT Administrations.

Subject: Standard Operating Procedure for the process of registration of vehicles imported by the Vehicle Manufacturers or through their authorized representatives in India

Sir/Madam,

The Ministry of Road Transport and Highways through an amendment in the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (CMVR) made through GSR 870(E) dated 13th September, 2018 (Copy enclosed) has provisioned for the import of certain limited number of vehicles under various categories by the vehicle manufacturer directly or through their authorized representative for the purpose of further sale or research or by the organization / citizen for personal use, demonstration, testing, research or scientific use.

2. With the Ministry's online registration of vehicles system provided through NIC viz. VAHAN system in operation in the States, the process of registration of vehicles is being carried through an IT based system. The system is linked with the homologation system being provided by the Ministry through NIC, wherein the domestic vehicle manufacturer provides the details of each vehicle sold in the country and those details are used by the dealers selling the vehicles to the citizens. Further, the Registering Authorities also uses the same details for completing the process of Registration of Vehicles. The system is secured, with only the authenticated users having access to the system for updating.

3. With the requirement to facilitate the Vehicle Manufacturers / Importers or organisations / citizens to have the vehicles so imported as per the above said notification, be registered and further that the details of the vehicles are captured properly, a facility is being provided through VAHAN.

4. The Standard Operating Procedure for the process is hereby attached to be followed for the process of registration for such vehicles imported as per GSR 870 (E) dated 13th Sep 2018 by the Vehicle Manufacturers or through their authorized representatives in India or by the organization / citizen for personal use, demonstration, testing, research or scientific use.

5. It is also requested that the registering authorities in the State be directed to ensure that the information on customs duty payment and clearance from Directorate General of Foreign Trade (DGFT) must be checked before permitting registration.

Yours faithfully,



(Dharkat R. Luikang)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph.No. 011-23715211
Email: dharkat@nic.in

Encl: 1. Copy of GSR 870 (E), 13th September, 2018
2. Standard Operating Procedure

Copy to:

1. Director, CIRT (Central Institute of Road Transport) for information and necessary action.
2. DDG, National Informatics Centre, Delhi
3. Directors of ARAI, ICAT, VRDE and other Testing Agencies under CMVR 1989
4. DG, Society of Indian Automobile Manufacturers, New Delhi
5. CEO, Federation of Automobile Dealers Association, Delhi

Copy to: Director General of Foreign Trade, New Delhi



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940

No. 636]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 870(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 528(अ) तारीख 6 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 6 जून, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 92 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) जब कोई भाग, संघटक या संयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानक इन नियमों में अधिसूचित मानक के स्थान पर अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी की अनुपालना करता है, ऐसे भाग, संघटक या संयोजन की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक के अनुपालन प्रमाणपत्र के लिए नियम 124 और नियम 126 के प्रयोजन के लिए स्थापित समझा जाएगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 126 के दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि यान विनिर्माता, जो अनुप्रयुक्त पूर्णतया निर्मित इकाईयों (सीबीयू) या पूर्णतया नॉकड डाउन इकाईयों (सीकेडी), जो दाएं हाथ के स्टीयरिंग नियंत्रण यान है, का प्रत्यक्षतः या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से यथास्थिति, एम 1 या एल प्रवर्ग के यानों की 2500 इकाईयों का और अन्य प्रवर्गों के यानों की 500 इकाईयों का आयात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानकों का अनुपालन करते हैं, ऐसे यानों की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक अनुपालन प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन विक्रय और रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि दाएं हाथ के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले अनुप्रयुक्त यानों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक, अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानक के हैं, जिनका भारत में पूर्णतया निर्मित इकाईयों (सीबीयू) के रूप में वैयक्तिक उपयोग, प्रदर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक कार्यों के लिए आयात किया जाता है, ऐसे यानों की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक अनुपालना प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि संनिर्माण उपस्कर यान (सीईवी) का स्टीयरिंग नियंत्रण किसी भी एक तरफ हो सकेगा :

परंतु यह भी कि ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस), किस्म अनुमोदन प्रक्रिया 115/116, भारतीय मानक (आईएस) और मानकीकरण मानक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएसओ) जिनको केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन अधिसूचित किया गया है, के शुद्धिपत्र, संशोधन या पुनरीक्षण पुनरीक्षण से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया एआईएस-000 : 2013 के अनुरूप होगी।”।

[फा. सं. आरटी-11036/82/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पणः— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 749 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2018

G.S.R. 870(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 528 (E), dated the 6th June, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 6th June, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.**- These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 92, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely. -

"(3) Whenever a part, component, or assembly is compliant with the international standard namely, EEC or ECE or Japanese, in lieu of the standard notified in the rules, the compliance of such part, component or assembly shall be deemed to be established for the purpose of rules 124 and 126, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency."

3. In the said rules, in rule 126, for the second proviso, the following shall be substituted, namely: -

"Provided further that in respect of vehicle manufacturer, importing into India unused completely built units (CBU) or completely knocked down units (CKD) of right-hand steering control vehicles, directly or through their authorised representative, up to 2500 units of M1 or L category of vehicles, as the case may be, and up to 500 units of other categories of vehicles annually, compliant with the international standard, namely EEC or ECE or Japanese, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for sale and registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorized agency or accredited certifying agency:

Provided also that in respect of unused right-hand steering control vehicles compliant with the international standard namely, EEC or ECE or Japanese, imported into India as completely built units (CBU), for the purpose of personal use, demonstration, testing, research or scientific work, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Provided also that the construction equipment vehicles (CEV) may have steering control on either of the side:

Provided also that the administrative procedure to deal with corrigendum, amendments or revisions to Automotive Industry Standards (AIS), Type Approval Procedures 115/116, Indian Standards (IS) and International Organisation for Standardisation (ISO) standards, which are notified under the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall be in accordance with AIS-000: 2013."

[F. No RT-11036/82/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 749(E) dated the 7th August, 2018.

Standard Operating Procedure (SOP) for the process of registration of vehicles imported by the vehicle manufacturers or through their authorised representatives in India or by the organisation / citizen for personal use, demonstration, testing, research or scientific use etc.

Introduction

The Ministry of Road of Road Transport and Highways through an amendment in the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (CMVR) made through GSR 870 (E) dated 13th Sep 2018 has provisioned for the import of certain limited number of vehicles under various categories by the vehicle Manufacturer directly or through their authorised representative for the purpose of further sale or research, or by the organisation / citizen for personal use, demonstration, testing, research or scientific use.

With the Ministry's online registration of vehicles system provided through NIC viz. VAHAN 4 system in operation in the States, the process of registration of vehicles is being carried through an online process. The system is linked with the homologation system being provided by the Ministry through NIC, wherein the domestic vehicle manufacturer provides the details of each vehicle sold in the country and that detail is used by the dealers selling the vehicles to the citizens. Further, the Registering Authorities also uses the same details for completing the process of Registration of Vehicles. The system is secured, with only the authenticated users having access to the system for updating.

Purpose and Scope

The homologation portal under VAHAN helps in maintaining transparency, genuineness and standards in a motor vehicle.

There is now a requirement for providing facilitation to the Vehicle Manufacturers / Importers or organisations / citizens to have the vehicles so imported be registered through VAHAN and further that the details of the vehicles are captured properly in VAHAN.

Key Objectives

- To facilitate the process of registration of vehicles so imported.
- To ensure that the correctness of details entered in the VAHAN database.

RT-11036/82/2017-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
Transport Bhawan, New Delhi 110001

SOP for the process of registration of Imported Vehicles

- To Maintain common standard across the country amongst various stake holders.
- To ensure that only the authenticated importer is able to have the vehicles registered in India.
- To ensure that only the limited number of vehicles allowed to be imported under the rules or the policy under the category allowed are registered.

Standard Operating Procedure

The following would be the Standard Operating Procedure with the roles and responsibilities for the process:

Stages	Manufacturer / representatives / citizens	MORTH / CIRT	NIC
Stage - 1 (Homologation portal for Imported Vehicles)	The Vehicles are imported and registered through CMVR, 1989 as per GSR-870(E), dated 13 th Sept 2018	MORTH - Provisions of CMVR, 1989 are complied with.	Provide technical support to stake holders by developing the software and providing support for the homologation module for facilitating the registration of Imported vehicles.
Stage- 2 (Login Credential)	• The company / firm wishing to Import or already imported has to apply in the prescribed proforma as attached for obtaining a login credential for homologation to the Director, Central Institute of Road Transport (CIRT). This would be done online uploading all relevant documents or providing a	CIRT will examine the applications with relevant documents and send an approval, digitally signed, to NIC	NIC will provide login credentials to the respective manufacturer

RT-11036/82/2017-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
Transport Bhawan, New Delhi 110001

SOP for the process of registration of Imported Vehicles

Stages	Manufacturer / representatives / citizens	MORTH / CIRT	NIC
	request to the Director, CIRT, Pune. Intimation would be sent to CIRT as and when application is made online. - The following are mandatory- (i) CIN /LLPIN of the company (ii) IEC Code: This is a Computer generated number as per procedure outlined in the Handbook of procedure of DGFT mandatory for undertaking any export/import activities. (iii) Date of Incorporation of a Company [as per Companies Act 2017 & Details of registered office. Note- - There would be NO requirement for an 'individual' importing to obtain a login credential.		
Stage - 3 (TAC uploading and approving)	Manufacturer will upload the TAC (Type Approval Certificate) given by the authorised agency or accredited certifying agency and map with the master form by providing	The Central Institute of Road Transport, Pune (CIRT) will approve the details provided in TAC and the	

RT-11036/82/2017-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
Transport Bhawan, New Delhi 110001

SOP for the process of registration of Imported Vehicles

Stages	Manufacturer / representatives / citizens	MORTH / CIRT	NIC
	all the technical parameters required.	uploaded technical parameters of each model of the Motor Vehicle so uploaded by the Importer. • For an Individual importing the vehicle, would apply online on VAHAN under the category of 'Registration of Imported Vehicle' and upload the relevant papers. This would be passed on to CIRT to validate who would enter the vehicle parameters on the Homologation portal for the vehicle under the 'Individual Import category'. • An	

RT-11036/82/2017-MVL
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
Transport Bhawan, New Delhi 110001

SOP for the process of registration of Imported Vehicles

Stages	Manufacturer / representatives / citizens	MORTH / CIRT	NIC
		application fee of Rs. 10,000/- for each model may be charged by CIRT from the Manufacturer or Individual.	
Stage - 4 (inventory details uploading)	The Manufacturer will upload inventory details in respect of their models and class of vehicles.		All the details uploaded by a manufacturer / importer are made available for registration. To ensure that specified number of vehicles of particular manufacturer in a year are registered must be validated as per the rules.

A weblink for the process would be made available in the website of the Ministry
and on VAHAN which provides the details of this procedure.



Format of application for Login Id creation for the “National Transport Portal” for uploading inventory of the Imported vehicles to be submitted by the Companies or Firms Importing vehicles into India on official letter heads

REQUESTING: ☐ New Login Id Creation

☐ Modify Information

1. Name of Applicant Organisation:

2. Name of Officer Applying

3. Designation of Officer:

4. Office Address:

City & PIN Code:

5. Telephone No:

(O)

(Mob)

6. E-Mail Id:

7. FAX No:

8. Current/Prior Login ID (if any):

9. Documents Attached :

Note: 1. The application should be submitted by the Head office on official letter head to the Director, Central Institute of Road Transport (CIRT), Pune, Maharashtra

2. CIRT will verify and approve the applications. Once approved, the applications will be sent to NIC for creation of User ID and Password.

3. Only one user id/ password will be issued to an organization by NIC. The organisation may, in turn, create sub user ids and passwords, if required, for its constituents/branches etc. Prescribed terms and conditions for the acceptance of the documents are attached.

Signature of the Applicant
Date

Seal

For CIRT / NIC use

**The given information verified and login id be created on the portal
<https://vahan.parivahan.gov.in/makermode1>**

Application No: _____

**Signature of CIRT
Official with date and seal**

For CIRT / NIC use

**The given information verified and login id created on the portal
<https://vahan.parivahan.gov.in/makermode1>**

Login Id Given: _____

Application No: _____

**Signature of NIC
Official with date and seal**

TERMS AND CONDITIONS

1. Users are requested to keep the given Login id and password a secret.
2. Please change your password immediately. Thereafter change the password as frequently as possible, at least once in every three months.
3. Not doing 1 & 2 above may compromise security on account of hackers. Hackers can use the same account for getting vehicle information. **NIC is neither responsible nor accountable for any type of misuse of the compromised user accounts. Detection of misuse by automated monitoring tools may result in deactivation of the account.**
4. Users are requested, to install the personal firewall software to secure their machine.
5. Users are requested to install the Antivirus software with latest pattern update periodically and OS patches in their system.
6. NIC will take all possible measures to prevent data loss, however, due to unforeseen technical issues, if the same happens, MORTH or NIC cannot be held responsible.
7. Applicant shall maintain the security and integrity of information received. **MORTH / NIC is neither responsible nor accountable for any type of misuse of the compromised user accounts.**
8. Applicant shall maintain and update current list of persons and entities authorized to access the information or to whom such information may be disclosed. This list shall be made available to MoRTH/NIC upon request.
9. Applicant shall not use, sell, retain, distribute, provide, or transfer any restricted information or portion of such information accessed except as authorized by the MORTH/NIC.
10. The NIC on behalf of MoRTH reserves the right to audit Applicant's compliance with set rules/acts.
11. The applicant understands and agrees that NIC shall not be liable for any damages arising out of or in any way connected with applicant's access or use of information.

We accept the above terms and conditions.

Signature: _____

Name: _____

Date: _____

Seal

Note: Kindly send approval letter from the concerned organization on letter head along with this application to respective Authorised Signatory. List of Authorised Signatory along with Postal Address can be found on the link available on <https://vahan.parivahan.gov.in/makermode1>